भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3212
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक

3212. श्री गौरव गोगोई:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को पता है कि हाल के वर्षों में लैंगिक असमानता संबंधी भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है, जो महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण में आई गिरावट को दर्शाती है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में बढ़ते लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए उठाए गए उपायों, का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में गिरती रैंकिंग के लिए जिम्मेवार किसी विशिष्ट कारक की पहचान की है और यदि हां, तो पहचाने गए उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता है;
- (घ) क्या सरकार के पास प्रगति की निगरानी करने और चिंताजनक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए लैंगिकतः वर्गीकृत डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कोई उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार लैंगिक समानता पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन किस तरीके से कर रही है; और
- (च) यदि हां, तो इस संबंध में प्रगति के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए लागू किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (च) : वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2024 को गैर-सरकारी संगठन वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसने वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (जीजीजीआई) में भारत को 146 देशों में 129वें स्थान पर रखा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को 146 देशों में से 127वें स्थान पर तथा 2022 में 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया था।

भारत सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को कम करके तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ाकर भारत में लैंगिक अंतर को

पाटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

आर्थिक सशक्तीकरण

सरकार ने श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहलों की हैं। श्रम कानूनों में महिला श्रमिकों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं, साथ ही श्रम कानूनों के तहत अन्य सभी अधिकार भी हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मातृत्व लाभ अधिनियम को 2017** में संशोधित कर दो जीवित बच्चों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इसमें महिला द्वारा मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद "घर से काम" करने का प्रावधान भी किया गया है, बशर्ते सोंपे जाने वाले काम की प्रकृति हो, अवधि के और शर्तों पर नियोक्ता और महिला कर्मचारी परस्पर सहमत हों।
- सरकार ने चार श्रम संहिताएं अर्थात् **वेतन संहिता 2019; औद्योगिक संबंध संहिता 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 भी लागू की हैं**, जो अन्य के साथ-साथ कई प्रावधानों जैसे वेतन, भर्ती और रोजगार की शर्तों से संबंधित मामलों में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना; महिलाओं को उनकी सहमति और अन्य पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी सभी प्रकार के काम के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित करने का अधिकार के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देते हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- **सखी निवास** (कामकाजी महिला छात्रावास) योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराती है और इस तरह अधिक महिलाओं को रोजगार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **पालना**, राष्ट्रीय क्रेच योजना, यह सुनिश्चित करती है कि महिलाएं बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और प्रेरक वातावरण प्रदान करके लाभकारी रोजगार प्राप्त करें।
- मिशन शक्ति के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर **महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एचईडब्ल्यू)** को मंजूरी दी गई है। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ने, मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है, जिसमें देश भर में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक समान पहुंच शामिल है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पीएमएमवाई के तहत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक का बिना किसी जमानत के ऋण दिया जाता है ताकि वे अपनी व्यावसायिक कार्यकलाप को स्थापित या विस्तारित कर सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना** महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों अर्थात्, जनसंख्या के वे वर्ग जो सलाह/मार्गदर्शन की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और विलंबित ऋण के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं, के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** का उद्देश्य महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है।
- **दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन** महिलाओं के लिए कौशल विकास के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे बाजार आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना** का उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्ति के एकल और संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहित करके महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को प्रोत्साहित करना है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना** - इस योजना के तहत बालिकाओं के बैंक खाते खोलकर परिवारों को बालिकाओं के भविष्य में वित्तीय निवेश करने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।
- **कौशल उन्नयन एवं महिला कॉयर योजना** एमएसएमई का एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कॉयर उद्योग में कार्यरत महिला कारीगरों का कौशल विकास करना है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरईजीए)** में यह अधिदेशित किया गया है कि इस योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत सृजित रोजगारों में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को दी जानी चाहिए।

राजनीतिक सशक्तीकरण

- देश में वर्तमान में इस समय एक महिला राज्य प्रमुख है।

- जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं। पंचायती राज मंत्रालय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) सहित पंचायत हितधारकों का क्षमता निर्माण महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। आज, पीआरआई में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 14 लाख या 46% महिलाएं हैं, जो संवैधानिक अधिदेश से बहुत अधिक है, और वैश्विक स्तर पर स्थानीय सरकारों में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है।
- वर्ष 2023 में, भारत की संसद ने संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पारित किया, जो संघीय ढांचे के सभी स्तरों पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह ऐतिहासिक कानून संसद के निचले सदन, लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित सभी संघीय राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, इस प्रकार सार्वजनिक निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाता है।

शिक्षा

- **समग्र शिक्षा:** स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना, यानी "समग्र शिक्षा" शुरू की है। इस योजना में "सर्व शिक्षा अभियान" (एसएसए), "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" (आरएमएसए) और "शिक्षक शिक्षा" जैसी तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं।
- स्कूलों में बालिकाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की दर को कम करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यकलापों को लक्षित किया गया है। समानता के लिए इसमें राज्य द्वारा निर्धारित पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की बालिकाओं को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें और वर्दी का प्रावधान करना, सभी स्कूलों में जेंडर के आधार पर अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान, बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, कक्षा VI से XII तक की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान, कक्षा I से कक्षा XII तक सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) बालिकाओं को वजीफा, दूरदराज/पर्वतीय क्षेत्रों/दुर्गम भूभाग वाले क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, इनसेनेटर(भस्मक), सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने जैसी विशेष परियोजनाएं शामिल हैं।
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम - एनआईएलपी): भारत संघ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने और देश भर में गैर-साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका नाम है - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम - एनआईएलपी) 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वयन अवधि के दौरान 1037.90 करोड़

रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के तहत 5.00 करोड़ गैर-साक्षर लोगों को कवर किया जाएगा।

- **स्वच्छ विद्यालय मिशन** के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि अगस्त, 2015 तक सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए कम से कम एक कार्यशील शौचालय हो। यूडीआईएसई+2021-22 के अनुसार, 97.48% सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा है और 98.2% सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है।
- 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में बालिकाओं के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए 2020 में **विज्ञान ज्योति** शुरू की गई, जिससे 80,000 से अधिक छात्राएं लाभान्वित हुईं।
- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) (2020)** यह पहल एसटीईएम क्षेत्र में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में संस्थागत स्तर पर परिवर्तनकारी बदलावों को प्रोत्साहित करती है। अपने पायलट चरण में, 30 वैज्ञानिक संस्थान एसटीईएम में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में जीएटीआई पायलट के तहत काम कर रहे हैं।
- **महिला प्रौद्योगिकी पार्क (2017-18)** को संसाधन केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया है, जहां महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, विभिन्न प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण पर सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लैंगिक आधार पर अलग-अलग आंकड़ा एकत्र करते हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण और जनगणना करके भी लैंगिक आधार पर अलग-अलग आंकड़ा एकत्र किया जाता है।

सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) के अंतर्गत, देश में सुधार एवं विकास को आगे बढ़ाने तथा सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों की निगरानी का लाभ उठाने का निर्णय लिया गया है।